विचार बिन्दु

समस्त महान गलतियों की तह में अभिमान ही होता है। –रस्किन

लाख छुपाए छुप न सकेगा....

राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है कि किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा एवं वहां फोटो और वीडियो बनाने पर रोक होगी। इसका उद्देश्य छात्र-छात्राओं की निजता और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना बताया गया है। यह आदेश न केवल अविवेकपूर्ण है, अपितु किसी भी लोकतांत्रिक, कल्याणकारी सरकार के लिए आवश्यक पारदर्शिता के एकदम विपरीत है। सरकार, विशेष कर प्रधानमंत्री जी बार-बार यह कह चुके हैं कि समाज के प्रबुद्ध लोगों को अपने पास के विद्यालय में शैक्षिक स्तर को सुधारने एवं आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए योगदान करना चाहिए। राजस्थान सरकार स्वयं, प्रतिवर्ष भामाशाहों को सम्मानित करती रही है।

राजस्थान में स्वैच्छिक संगठनों की सरकार के साथ मिलकर कार्य करने की स्वस्थ परंपरा रही है। इन्होंने कई शैक्षिक नवाचार किए जिनकी सराहना देश विदेश में हुई। लोक जुंबिश और शिक्षा कर्मी परियोजनाओं में स्थानीय समुदाय की भागीदारी विद्यालय संबंधित निर्णय लेने में बढ़ाई गई। इन परियोजनाओं और साक्षरता अभियान में जनसमुदाय की प्रभावी भागीदारी का ही परिणाम था कि नब्बे के दशक में राजस्थान ने साक्षरता, विशेषकर महिला साक्षरता में देश में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की।

शिक्षा मंत्री का वर्तमान आदेश इन सभी पूर्व प्रयासों पर पानी फेर देता है एवं अपारदर्शिता की नई मिसाल प्रस्तुत करता है । यह एक तथ्य है कि राजस्थान में शिक्षा की स्थिति, विशेष कर प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। हजारों स्कूल भवन जर्जर अवस्था में है। झालावाड़ में तो छत गिरने से कई बच्चों की मौत हो गई थी। हजारों स्कूलों में न लड़कियों के लिए शौचालय है, न पीने का शुद्ध पानी, न बैठने के लिए बेंच है और न ही पर्याप्त शिक्षक हैं। सैकड़ों विद्यालय, बिना शिक्षकों के हैं वहीं दूसरी ओर ऐसे भी विद्यालय हैं जो केवल कागजों में हैं और वहां शिक्षक भी पदस्थापित हैं जो प्रतिमाह निरन्तर वेतन प्राप्त कर रहे हैं। यही कारण है कि 'प्रथम' द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षा के स्तर से सम्बन्धित सर्वे 'असर' (Annual Status ofEducation Report) में राजस्थान के बच्चों की शैक्षिक स्थिति खराब रही है। जब मीडिया के लोग खराब स्थिति के बारे में सबको जानकारी देते हैं तो कई बार सरकार स्वयं पहल करके उन्हें ठीक करने का प्रयास करती रही है ।

हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी ने 'स्कूल ठीक करो' अभियान 15 अगस्त से देश में प्रारंभ किया है। अभिजीत दीपके ने सभी लोगों से अपील की है कि वे अपने समीप के स्कूलों में जाएं और वहां पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, शिक्षकों की स्थिति और शैक्षिक स्तर की जानकारी प्राप्त करके उसके फोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करें। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए नागरिकों का योगदान लेना और सरकार का ध्यान स्कूलों की कमियों की ओर आकर्षित करना है ताकि सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिक दे और विद्यालय के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए। सामान्यतया, सरकार को इस अभियान का स्वागत करना चाहिए था क्योंकि इससे विद्यालयों की वास्तविक स्थिति से सरकार अवगत होती।

शिक्षा मंत्री की शायद यह सोच है कि स्कूलों की कमियों को मीडिया से छुपाया जा सकता है और इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। पता नहीं, वे किस कल्पना लोक में रहते हैं। शायद उन्हें नहीं पता कि आज के तकनीकी युग में कोई भी बात किसी से छुपी नहीं रह सकती है और वह क्षण भर में पूरे विश्व में फैल सकती है। शिक्षा, सरकार के लिए प्राथमिकता नहीं रही है जबकि देश को विकसित बनाने के लिए यह अनिवार्य है। अतः नागरिकों को ही इसमें पहल करके सरकार पर आवश्यक कदम उठाने हेतु दबाव बनाना होगा। यह तभी संभव है, जब स्कूल के दरवाजे सभी आम नागरिकों और मीडिया के लिए सदैव खुले रहें ताकि वे देख सकें कि स्कूलों की वास्तविक स्थिति क्या है? जब कोई सरकार अच्छा काम करती है तो मीडिया को स्वयं आमंत्रित करके उसे दिखाती है, ताकि अपनी छवि का निर्माण कर सके। यह संभव नहीं है कि आप मीडिया का इस्तेमाल अपनी इच्छानुसार करें। उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी होगी।

कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा नागरिकों से अपने स्कूलों को देखने की अपील का सरकार को स्वागत करना चाहिए था एवं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए था। एक प्रकार से उन्हें वास्तविक जानकारी स्कूलों के बारे में लाखों नागरिकों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती थी। सरकार ने इसके ठीक विपरीत लोगों को विद्यालय में जाने से वंचित करके अपनी कमियों को छुपाने का असफल प्रयास किया है। कितनी विडंबना है कि भाजपा सरकार का ही रेल मंत्रालय तो यात्रियों से आग्रह करता है कि यदि वे ट्रेन की सफाई, खाने आदि की गुणवत्ता में कमी देखें तो उसका फोटो, वीडियो बनाकर उन्हें भेजें। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उन्हें ऐसा करने से मना किया जा रहा है। कहा जाता है कि गलीचे के नीचे जमी मिट्टी को नहीं हटाएंगे तो वह वहां जमा होती रहेगी और इतनी अधिक हो जाएगी कि उसे बाद में साफ करना बहुत मुश्किल होगा।

शिक्षा मंत्री ने अपने बयान के बचाव में कहा कि लोग अनुमति लेकर के विद्यालय में जा सकते हैं। जो प्रधानाचार्य विद्यालय की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, वे भला किसी को अंदर आकर फोटो खींचने की अनुमति क्यों देंगे? पहले ही वे बाहर के लोगों का विद्यालय में आना पसंद नहीं करते थे और किसी न किसी बहाने उन्हें टालते थे, अब तो मंत्री जी के आदेश का सहारा और मिल गया है।

शिक्षा मंत्री जी वास्तव में स्कूलों की हालत ठीक करना चाहते तो नागरिकों और मीडिया को विद्यालय में आने को प्रोत्साहित करने हेतु निर्देश प्रधानाचार्यों को जारी करते। इस पारदर्शिता से वे विद्यालयों की स्थिति को बेहतर करने की दिशा में सरकार पर दबाव बनाने का ही कार्य कर सकते थे। तब इसके लिए वित्त विभाग को पर्याप्त राशि शिक्षा हेतु उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होना पड़ता। क्या शिक्षा मंत्री जी को अपने सरकारी स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलने का इतना अधिक डर है?

सरकार का यह आदेश वैसे भी निरर्थक और बेमानी लगता है क्योंकि आप किस-किस पर रोक लगाएंगे? क्या शिक्षकों को विद्यालय में मोबाइल ले जाने से वंचित करेंगे? आजकल किसी भी समय पर किसी भी स्थान का वीडियो बनाकर कोई भी व्यक्ति मोबाइल पर अपलोड कर सकता है। क्या जो शिक्षक ऐसा करेंगे उन पर सरकार अनुशासनिक कार्रवाई करेगी?

पाठकों के लिए यह जानना रुचिकर होगा कि राजस्थान, शिक्षा प्रबंधन में समाज को जोड़ने की दृष्टि से पहल करने वाला प्रदेश रहा है। लोक जुंबिश और शिक्षा कर्मी जैसी परियोजना में तो स्थानीय समुदाय के सहयोग से शिक्षकों का चयन तक किया जाता था। स्थानीय समुदाय की पूरी भागीदारी विद्यालय को संचालित करने में सुनिश्चित की गई थी।

यह विडंबना है कि जिस राजस्थान में "सूचना के अधिकार कानून" का आंदोलन प्रारंभ हुआ और अंततः जिसे इस कानून का रूप मिला, उसी प्रदेश में नागरिकों को सूचना प्राप्त करने से वंचित किया जा रहा है । "सूचना का अधिकार" कानून का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को पता लगे कि सरकार का कामकाज कैसे चल रहा है, कोई भी निर्णय किस प्रकार से लिए जा रहे हैं एवं उनके पैसे का सरकार किस प्रकार से उपयोग या दुरूपयोग कर रही है? यह सबको पता है कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के शैक्षिक उपकरण, कंप्यूटर आदि विद्यालयों में बरसों बेकार पड़े रहते हैं। सरकार अपने संसाधनों के दुरुपयोग के बारे में अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकती थी, यदि वह मीडिया और नागरिकों को विद्यालय में जाकर, वहां की स्थिति को पता करने के लिए प्रोत्साहित करती । मंत्री जी के इस आदेश से तो इसका ठीक उल्टा काम हो रहा है।

यह बात भी सत्य है कि अपवादों को छोड़कर, अच्छे वेतन के बावजूद, शिक्षक अपने कार्य को गंभीरता से नहीं लेते हैं और इस कारण शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। सरकार को शैक्षिक स्तर को बेहतर करनकरने और विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को अच्छा करने पर ध्यान देना चाहिए न कि इन कमियों को उजागर करने वालों को प्रतिबंधित करना चाहिए। पता नहीं, किन लोगों की सलाह पर शिक्षा मंत्री जी ने इस प्रकार का आदेश जारी किया है? यह आदेश केवल तानाशाही पूर्ण रवैया दर्शाता है। यह भी सिद्ध करता है कि सरकार कैसे स्वयं को जनता से दूर करती जा रही है? सरकार को नागरिकों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे उनके कार्य में भागीदार बनें । जन भागीदारी, सशक्त लोकतंत्र और सुशासन की पहली पहचान है। मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, को आप रोक देंगे तो, आप अपना स्वयं का ही नुकसान करेंगे ।

सरकार का यह आदेश वैसे भी निरर्थक और बेमानी लगता है क्योंकि आप किस-किस पर रोक लगाएंगे? क्या शिक्षकों को विद्यालय में मोबाइल ले जाने से वंचित करेंगे? आजकल किसी भी समय पर किसी भी स्थान का वीडियो बनाकर कोई भी व्यक्ति मोबाइल पर अपलोड कर सकता है। क्या जो शिक्षक ऐसा करेंगे उन पर सरकार अनुशासनिक कार्रवाई करेगी ?

सरकार को समझना होगा कि अधिकारियों द्वारा भेजे गए आंकड़े धरातल की वास्तविक स्थिति से बहुत दूर होते हैं। डर के मारे शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को वही बात बताते हैं जो वे सुनना पसंद करते हैं। शिक्षा मंत्री ने इस आदेश से यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें सच्चाई जानने में कोई रुचि नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है "shooting the messenger" अर्थात आप को जो व्यक्ति ऐसी जानकारी दे जो आपको पसंद ना हो तो आप उस पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने के बजाय संदेशवाहक को ही मार देते हैं। मंत्रीजी का आदेश यही काम कर रहा है।

शिक्षा मंत्री जी के इस आदेश के ही कारण जब कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका और उनके साथियों ने जयपुर के कंवरपुरा के भैंसों के तबेले में चल रहे विद्यालय में जाकर वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया तो असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। उनकी कारों पर पत्थर फेंके गए जिससे कई लोगों को चोट लगी। प्राप्त समाचार के अनुसार हमला करने वाले लोग सत्ताधारी दल के इशारे पर यह काम कर रहे थे। मंत्रीजी ने तो इस काम के लिए उन्हें बधाई तक दे डाली। यह गंभीर चिंता का विषय है ।

विद्यार्थियों की निजता की सुरक्षा की बात करना वैसे भी सरकार को शोभा नहीं देता। क्या शिक्षा मंत्री को नहीं पता है कि विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा यौन शोषण के मामले सामने आते रहे हैं? इस प्रकार के मामलों को सामने लाना गलत है या ऐसे मामलों का होना गलत है?

मीडिया को चाहिए कि वह शिक्षा विभाग के किसी भी कार्यक्रम में तब तक भाग न ले जब तक कि शिक्षा मंत्री इस आदेश को वापस न ले लें।

सरकारी विद्यालय में शिक्षा की खराब स्थिति इससे भी स्पष्ट होती है कि सरकारी शिक्षकों के स्वयं के बच्चे इनमें पढ़ाई नहीं करते हैं। क्या शिक्षा मंत्री जी यह सर्वे कराएंगे कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों में से कितने प्रतिशत के बच्चे राजकीय विद्यालयों में अध्यनरत हैं ?

संभव है, शिक्षा मंत्री से प्रेरणा लेकर स्वास्थ्य मंत्री भी इसी प्रकार का आदेश जारी कर दें ताकि अस्पताल में बे मौत मरने वालों की खबर लोगों तक नहीं पहुंचे।

परेशानी का कारण यह भी है कि इतना सब होने के बाद भी मुख्यमंत्री की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया और न इस आदेश को वापस लेने के लिए शिक्षा मंत्री को कहा गया है। इस आदेश से लोकतंत्र में लोक की ही अवमानना हुई है।

अंत में हम यही कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री चाहे जितना भी जोर लगा लें,आज के सोशल मीडिया के जमाने में न कोई बात छुपी है ना छुपी रह सकती है । हमें तो यह गाना बरबस याद आ जाता है – लाख छुपाए छुप ना सकेगा ....

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

सरकारी स्कूलों में प्रवेश पर पहरा : सुरक्षा के नाम पर पारदर्शिता से दूरी क्यों ?

राजेन्द्र जोशी

सरकारी स्कूलों में अब बिना अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी राजस्थान सरकार के आदेश ने शिक्षा जगत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार का तर्क यदि विद्यार्थियों की सुरक्षा और विद्यालयों में अनुशासन सुनिश्चित करना है तो यह स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण विषय है। बच्चों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या विद्यालयों के दरवाजे आम नागरिकों, अभिभावकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया के लिए बंद कर देने से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी? अथवा इसके पीछे सरकार की कोई दूसरी मंशा भी है, जिस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जानी चाहिए? विद्यालय केवल सरकारी भवन नहीं होता। वह समाज की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थाओं में से एक है। गांव और शहर का सरकारी स्कूल स्थानीय समाज, अभिभावकों और बच्चों के जीवन से सीधे जुड़ा होता है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। इसलिए सरकारी स्कूलों की स्थिति पर समाज की नजर रहना आवश्यक है।

ऐसे में प्रवेश के लिए पहले सक्षम स्तर से अनुमति लेने की अनिवार्यता कई आशंकाओं को जन्म देती है। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे की पढ़ाई, शिक्षक की उपलब्धता, विद्यालय में सुविधाओं या भवन की स्थिति को देखना चाहता है तो क्या उसे भी पहले अनुमति लेनी होगी? यदि किसी सामाजिक संस्था का प्रतिनिधि विद्यालय की व्यवस्थाओं का अध्ययन करना चाहता है तो क्या वह बिना पूर्व अनुमति के विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि मीडिया किसी सरकारी विद्यालय की वास्तविक स्थिति जानना चाहता है तो क्या उसे भी अनुमति की प्रक्रिया से गुजरना होगा?

सरकार के इस निर्णय के पीछे वास्तविक मंशा क्या है, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। पिछले कुछ समय से प्रदेश के अनेक सरकारी विद्यालयों में भवनों की स्थिति, जर्जर कक्षा-कक्षों, टूटती दीवारों, क्षितठास्त छतों और अन्य आधारभूत सुविधाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं। यदि किसी विद्यालय की इमारत वास्तव में जर्जर है तो उसे समाज से छिपाने के बजाय सरकार को उसकी मरम्मत करवानी चाहिए। जहां भवन मरम्मत योग्य नहीं है, वहां नया भवन बनाया जाना चाहिए। बच्चों को सुरक्षित वातावरण देना सरकार की जिम्मेदारी है। यह भी समझना होगा कि जर्जर भवन की तस्वीर सामने आने से समस्या पैदा नहीं होती, बल्कि समस्या पहले से मौजूद होती है। तस्वीर या समाचार केवल उस समस्या को समाज और प्रशासन के सामने लाता है। यदि किसी विद्यालय की दीवार टूट रही है, कक्षा-कक्ष की छत खराब है या बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो उसे छिपाने की बजाय तत्काल सुधारना चाहिए।

सरकार यदि विद्यालयों की वास्तविक स्थिति को लेकर चिंतित है तो उसे प्रवेश प्रतिबंधित करने के बजाय निरीक्षण व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। नियमित तकनीकी निरीक्षण हो, विद्यालय भवनों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए, मरम्मत के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए और प्रत्येक विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं की सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

सरकार के पास यदि हर जर्जर विद्यालय के भवन की तत्काल मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो उसे समाज से सहयोग मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। राजस्थान की सामाजिक परंपरा में भामाशाहों का योगदान कोई नई बात नहीं है। देश-दुनिया में रहने वाले मारवाड़ी समाज और स्थानीय भामाशाह शिक्षा के लिए हमेशा आगे आते रहे हैं। यदि सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अभियान चलाए और विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकताओं को सार्वजनिक करे तो समाज के लोग विद्यालयों के विकास में सहयोग करने के लिए आगे आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि विद्यालय समाज से जुड़े रहें, समाज से कटें नहीं। सरकारी स्कूलों की सबसे बड़ी चुनौती केवल भवन नहीं है। उससे भी बड़ी चुनौती लगातार घटता नामांकन और सरकारी विद्यालयों के प्रति कम होता विश्वास है। जब पहले ही बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों से हटाकर निजी विद्यालयों की ओर ले जा रहे हैं, तब ऐसे आदेश सरकारी स्कूलों और आम समाज के बीच दूरी और बढ़ा सकते हैं।

सरकारी विद्यालयों को समाज का विश्वास जीतने की आवश्यकता है। इसके लिए विद्यालयों के दरवाजे बंद करने के बजाय उन्हें समाज के लिए अधिक पारदर्शी बनाना होगा। अभिभावक विद्यालय में अपने बच्चे की पढ़ाई और वातावरण को समझ सकें, सामाजिक संस्थाएं सहयोग कर सकें और मीडिया विद्यालयों की उपलब्धियों के साथ-साथ कमियों को भी सामने ला सके-यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्वस्थ प्रक्रिया है।

मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण प्रहरी है। यदि किसी सरकारी विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य हो रहा है तो मीडिया को उसकी खबर समाज तक पहुंचानी चाहिए। यदि किसी विद्यालय में गंभीर कमी है तो उसे भी सामने आना चाहिए। कमियों को उजागर करना सरकार के खिलाफ अभियान नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने का माध्यम है। इसलिए यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि सरकारी विद्यालयों में मीडिया और आम नागरिकों की पहुंच को अनुमति आधारित बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? सुरक्षा की चिंता वास्तविक है तो सुरक्षा के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक नियम बनाए जा सकते हैं। पहचान-पत्र, प्रवेश रजिस्टर, निर्धारित समय और विद्यालय प्रशासन की निगरानी जैसे उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन पूरी तरह अनुमति आधारित व्यवस्था बनाना क्या उचित है?

लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है और सरकारी संस्थाएं जनता के पैसे से संचालित होती हैं। सरकारी स्कूल किसी बंद सरकारी कार्यालय की तरह नहीं हैं। वे समाज के बच्चों के लिए बने सार्वजनिक संस्थान हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा के साथ-साथ उनकी पारदर्शिता और सामाजिक निगरानी भी उतनी ही आवश्यक है।

सरकार को इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि इसका उद्देश्य वास्तव में बच्चों की सुरक्षा है या विद्यालयों की कमियों को सार्वजनिक होने से रोकना। यदि उद्देश्य सुरक्षा है तो सरकार को विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। यदि उद्देश्य अनुशासन है तो उसके लिए संतुलित नियम बनाए जा सकते हैं। लेकिन यदि इस आदेश का परिणाम यह होता है कि आम अभिभावक, सामाजिक संगठन और मीडिया सरकारी स्कूलों से दूर हो जाएं, तो यह शिक्षा व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज जरूरत सरकारी स्कूलों के दरवाजे बंद करने की नहीं, बल्कि उन्हें समाज के लिए खोलने की है। जरूरत है कि सरकार कहे-आइए, हमारे विद्यालय देखिए, कमियां बताइए, सुझाव दीजिए और सहयोग कीजिए। जर्जर भवन दिखे तो उसकी मरम्मत होगी, शिक्षक की कमी दिखे तो उसे दूर किया जाएगा और जहां नया भवन जरूरी है वहां निर्माण कराया जाएगा।

सरकार को अपने विद्यालयों पर पर्दा डालने के बजाय उनकी स्थिति सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। यदि सरकारी स्कूल मजबूत होंगे, सुरक्षित होंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे और समाज के प्रति जवाबदेह होंगे तो अभिभावक स्वयं अपने बच्चों को वहां भेजने के लिए प्रेरित होंगे। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन सुरक्षा और पारदर्शिता एक-दूसरे की विरोधी नहीं हैं। लोकतंत्र में सुरक्षा के नाम पर पारदर्शिता को कमजोर करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित भी हों और समाज के लिए जवाबदेह भी। आखिर राजस्थान में सरकारी स्कूलों के दरवाजों पर पहरा लगाने से ज्यादा जरूरी है कि उनकी दीवारें मजबूत हों, कक्षा-कक्ष सुरक्षित हों, शिक्षक पर्याप्त हों, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो और अभिभावकों का विश्वास कायम हो। यही सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बचाने और मजबूत करने का वास्तविक रास्ता है।

–राजेन्द्र जोशी,
शिक्षाविद-साहित्यकार

लंदन डायरी : बटलिन माइनहेड, जहाँ समुद्र, मनोरंजन और बचपन का अद्भुत संगम है

इंग्लैंड के समरसेट में ब्रिस्टल चैनल के किनारे बसा बटलिन माइनहेड रिसॉर्ट केवल एक हॉलिडे पार्क नहीं, बल्कि ब्रिटेन की हॉलिडे संस्कृति का जीता-जागता इतिहास है। 1936 में सर बिली बटलिन द्वारा शुरू किया गया यह रिसॉर्ट आज मनोरंजन की दुनिया की समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ 400 एकड़ में फैला है। बटलिन इंग्लैंड का सबसे पुराना और फेमस फॅमिली हॉलिडे ब्रांड है। माइनहेड इसका सबसे बड़ा और आकर्षक रिसोर्ट के रूप में प्रसिद्ध है। आज जब छुट्टियों में लोग शांति ढूंढते हैं, बटलिन शोर, हँसी और परिवार के साथ बिताए समय का महत्व याद दिलाता है। यह सिर्फ रिसॉर्ट नहीं, एक पूरी दुनिया है जहाँ हर उम्र का व्यक्ति फिर से बच्चा बन जाता है। 21 से 24 अगस्त तक अपना कार्यक्रम बनाकर 21 अगस्त को सपरिवार हम यहाँ पहुंचे। यह स्थल साउथ लंदन के हमारे घर से 325 किमी दूर है। दो बैडरूम का एक बहुत सुन्दर और समुद्र किनारे अपार्टमेंट हमने पहले ही बुक करा लिया था जहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी।

रिसॉर्ट में मनोरंजन के तमाम साधन जैसे स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, बुटीक, स्टाइल शो, कॉमेडी, म्यूजिक, झूले और आर्केड जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। रिसॉर्ट आमतौर पर प्राकृतिक वातावरण में बने होते हैं। बटलिन आज भी उन परिवारों को अपनी ओर खींचता है जो समुद्र किनारे छुट्टियां बिताना चाहते हैं। रिसॉर्ट आमतौर पर टूरिस्ट लोकेशन (पर्यटक केंद्र) पर बनाए जाते हैं। इनको बनाने के लिए बहुत अधिक जमीन की आवश्यकता होती है। यह महंगे और आलीशान होते हैं। आमतौर पर रिसॉर्ट में लोग घूमने, मौज मस्ती करने, हनीमून मनाने जाते हैं। हमने बच्चों के फेमस peppa pig, bingo, jack and the beanstalk आदि शो देखे जो काफी मजेदार और रोमांचक थे। रिसॉर्ट में हर शाम अलग अलग थीम पर मनरंजक कार्यक्रम आयोजित होते है। बच्चों के लिए स्केली एंड फ्रेंड्स, कॉमेडी मैजिक शो और लाइव म्यूजिक इवनिंग रोज होती है।

इन इवेंट्स में बच्चे अपना हुनर भी दिखाते है।

यहाँ Splash Waterworld -नामक इंग्लैंड का सबसे बड़ा इनडोर वॉटरपार्क में से एक है। Splash Waterworld में इनडोर गर्म पानी का पूल, चार बड़ी स्लाइड्स - Master Blaster, Black Hole, Space Bowl और Blue Comet की सुविधा सुलभ है जिसका बच्चे से बुजुर्ग तक लाभ उठाते है। हम ने भी splash water world के इनडोर वाटर पार्क में पानी के मध्य आराम से तैरते हुए चक्कर लगाएं। यहां 13 से अधिक वाटर स्लाइड्स वेव पूल, रिवर और बच्चों के लिए प्ले जॉन है। ठन्डे वातावरण में गर्म पानी के साथ यहां परिवार मौज़ मस्ती करते है। 2026 में यहाँ दो नई स्लाइड्स टूर्नीडॉ ट्विस्ट और रिपटाइड जोड़ी गई है जो रोमांच पसंद युवाओं को बेहद पसंद आ रही है।

The Home of Entertainment, रिसॉर्ट का सार्थक स्लोगन है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए पूरे दिन कार्यक्रम। यहाँ दिन-रात लाइव शो, म्यूजिक, कॉमेडी, सर्कस बहुत फेमस हैं। यह बच्चों के लिए स्वर्ग है। बटलिन माइनर हेड को बचपन का खजाना भी कहा जाता है। यहां तीन पीढ़िया एक साथ छुटियाँ मनाने आती है। रिसोर्ट में इनडोर गेम्स थियेटर शो, स्काईलाइन और एडवेंचर पार्क विशेष रूप से बच्चों को खास आकर्षित करते है। बच्चों के मनोरंजन और खेल के लिए अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक झूले लगे है। अचंभित करने वाला यह एक पर्यटक केंद्र है। यहाँ खाने-पीने की स्टालों सहित अनेक प्रकार के मनोरंजक खेल, विभिन्न प्रकार की रोजमर्रा के काम में आने वाली वस्तुओं की आकर्षक स्टालें और बहुत सारे झूले है। इन झूलों पर बैठने के लिए लाइन लगी रहती है। इंग्लैंड के अंग्रेज सैलानियों के साथ भारत सहित अन्य देशों के सैलानी अपने बच्चों के साथ बड़ी संख्या में इन झूलों का आनंद उठाते है। हम भी कई झुलों पर बैठे जिनमें रोमांचित करने वाले आकाशीय झूले भी शामिल है। ये इलेक्ट्रॉनिक झूले है जो रंग बिरंगे तो है ही साथ में अपनी बनावट के कारण मनभावक भी है। रिसॉर्ट से निकलते ही माइनहेड का सात मील लंबा ब्रिस्टल चैनल का रेतीला बीच प्राकृतिक सादगी के साथ सुकून भरे पल प्रदान करता है।

–बाल मुकुंद ओझा,
वरिष्ठ लेखक और पत्रकार

विराटनगर कस्बे में पैंथर की दस्तक से लोग दहशत में

पावटा, (निसं)। विराटनगर कस्बे के लक्ष्मीनाथ जी मोहल्ले में पैंथर की लगातार बढ़ती आवाजाही से लोगों में दहशत का माहौल है। रविवार देर रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच पैंथर ने मुकेश शर्मा के मकान की छत पर बंधे श्वान पर हमला कर दिया। अचानक हुई इस घटना से परिवार के लोग घबरा गए।

जानकारी के अनुसार मुकेश शर्मा के घर की छत पर रोजाना की तरह श्वान बंधा हुआ था। देर रात पैंथर दीवार फांदकर छत पर पहुंचा और कुत्ते पर झपट पड़ा। कुत्ते के जोर-जोर से चीखने की आवाज सुनकर घर के लोग जाग गए। परिजनों ने छत पर पैंथर को देखा तो नीचे से ही पत्थर फेंकते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों के शोर से घबराया पैंथर कुत्ते को घायल करने के बाद छत से छलांग लगाकर मौके से भाग गया। घटना के बाद परिवार में भय का माहौल बन गया। सुबह छत पर पैंथर के पंजों के स्पष्ट निशान भी मिले, जिससे उसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई। घटना की सूचना मिलने पर वनरक्षक प्रहलाद सहाय मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने छत पर मिले पंजों के निशानों को पैंथर के होने की पुष्टि की। वन विभाग की ओर से लोगों को रात के समय विशेष सावधानी बरतने और अकेले बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। मोहल्लेवासियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से रात के समय क्षेत्र में पैंथर की आवाजाही देखी और सुनी जा रही है। अब घर की छत पर पहुंचकर कुत्ते पर हमला करने की घटना से लोगों की चिंता और बढ़ गई है। लोगों ने वन विभाग से मांग की है कि पैंथर की लगातार बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए जल्द पिंजरा लगाया जाए, क्षेत्र में रात के समय गश्त बढ़ाई जाए और पैंथर को पकड़कर आबादी क्षेत्र से दूर किया जाए।

राशिफल मंगलवार 25 अगस्त, 2026

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2083, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 10:51 तक, आयुष्मान योग प्रातः 7:41 तक, बालव करण प्रातः 6:21 तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मकर, मंगल-मिथुन, बुध-सिंह, गुरू-कर्क, शुक्र-कन्या, शनि-मीन राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज त्रिपुष्कर योग सूर्योदय से प्रातः 6:21 तक है और रवियोग रात्रि 10:41 से आरम्भ होगा। आज भौम प्रदोष व्रत, माला गौरी पूजा है। आज द्वादशी तिथि में वृद्धि हुई है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:18 से 10:53 तक, लाभ-अमृत 10:53 से 2:05 तक, शुभ 3:40 से 5:16 तक।

राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:07, सूर्यास्त 6:51

मेष

व्यावसायिक एवं नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

वृष

व्यावसायिक कार्यों में सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

मिथुन

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

कर्क

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

सिंह

अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। घर-परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य योजना के संबंध एवं व्यावसायिक प्रयासों में उचित सोच-विचार हो सकता है।

तुला

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध शुभ संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

धनु

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मकर

मानसिक तनाव दूर होने लगेगा। मनःस्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

मीन

आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध शुभ संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।